नईदुनिया

समृद्ध किसान सशक्त मध्यप्रदेश

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता का नया मॉडल... पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश के 32 लाख किसानों को रियायती दरों पर सोलर पंप देने का लक्ष्य

अन्नदाता अब ऊर्जादाता; भारी खर्च से मुक्ति, खेतों को मिलेगी 24 घंटे निर्बाध बिजली

सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना से उठाएं सस्ती बिजली का लाभ

भोपाल

मध्यप्रदेश ने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग से बड़ी क्रांति की शुरुआत की है। सरकार नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से किसानों को ऊर्जादाता बना रही है। इसके लिए सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना शुरू की गई है।

यह योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनी है। इसके तहत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता का नया मॉडल स्थापित हो रहा है। सौर ऊर्जा अभियान के तहत पीएम कुसुम योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 32 लाख किसानों को रियायती दरों पर आधुनिक सोलर पंप दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों में 30 लाख सोलर पंप देने की विशेष कार्ययोजना को मंजूरी दी है।

इसके तहत हर साल 10-10 लाख सोलर पंप कनेक्शन दिए जाएंगे। इस कदम से किसानों को भारी बिजली बिलों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही, ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

मात्र 5 रुपये में... किसानों को मिलेगा स्थाई बिजली कनेक्शन और साथ में सब्सिडी भी

किसानों की सहूलियत के लिए ऊर्जा विभाग मात्र 5 रुपये में बिजली का स्थाई कनेक्शन दे रहा है। वर्तमान में किसानों को हर दिन 10 घंटे निर्बाध बिजली दी जा रही है। अटल कृषि ज्योति योजना के तहत 10 हॉर्सपावर तक के किसानों को बिजली बिल में भारी सब्सिडी मिल रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छोटे किसानों को 5 हॉर्सपावर तक के पंप पर पूरी तरह मुफ्त बिजली दी जा रही है। सरकार का अंतिम लक्ष्य किसानों को खेतों के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली देना है। इससे सिंचाई की लागत बहुत कम हो जाएगी।

सौर ऊर्जा से अन्नदाता को मिलेगी बड़ी राहत

1. सोलर पंप मिलने से किसानों की डीजल और बिजली पर निर्भरता खत्म होगी, जिससे खेती की लागत में हर महीने बड़ी बचत होगी।
2. बेहद मामूली शुल्क पर परमानेंट बिजली कनेक्शन मिलने से छोटे और सीमांत किसानों पर शुरुआती बुनियादी खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा।
3. एससी-एसटी वर्ग के 1 हेक्टेयर तक के किसानों को 5 हॉर्सपावर तक मुफ्त बिजली से सीधे आर्थिक राहत मिल रही है।
4. सोलर पंप और फीडर सुधरने से किसानों को रात के बजाय दिन में सुरक्षित और पर्याप्त सिंचाई करने का अवसर मिलेगा।

हर खेत तक पानी: सूक्ष्म सिंचाई में मध्यप्रदेश बना देश का अग्रणी राज्य

केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक से बदलेगी एमपी के खेतों की तकदीर

सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का संकल्प

भोपाल

मध्यप्रदेश की कृषि समृद्धि और हर खेत तक पानी पहुंचाने के संकल्प को जल संसाधन विभाग ने धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। इस दिशा में त्वरित कार्यप्रणाली के दम पर पिछले दो वर्षों के भीतर 7 लाख हेक्टेयर से अधिक नई सिंचाई क्षमता का विस्तार करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।

इस बड़ी उपलब्धि के चलते प्रदेश की वर्तमान सिंचाई क्षमता बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। सरकार ने अब आगामी वर्षों में प्रदेश का कुल सिंचित क्षेत्र 100 लाख हेक्टेयर करने का दूरगामी लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश की दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तकदीर बदलने के लिए तीन बड़ी राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। इनमें केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना और तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना शामिल हैं। इनके पूरे होने से मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़ अंचल की सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। माइक्रो इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) और टपक सिंचाई पद्धतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश वर्तमान में पूरे देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है, जिससे पानी की हर बूंद का अधिकतम उपयोग पक्का हो रहा है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना की शुरुआत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय जल डैशबोर्ड

बेहतर जल उपयोग दक्षता और बांधों के जल स्तर की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक अत्याधुनिक 'राज्य स्तरीय जल डैशबोर्ड' बनाने की आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है, जो सिंचाई प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाएगा। इसके साथ ही, नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सीधे वित्त पोषित करने की मंजूरी दी गई है, जिससे बजटीय रुकावटें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। सरदार सरोवर परियोजना पर हुए ऐतिहासिक निर्णय से मध्यप्रदेश को बड़ी वित्तीय राहत मिलने के साथ-साथ राज्य के जल, सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र को एक नई मजबूती मिली है, जिससे अंतिम छोर के खेतों तक पानी पहुंचना सुगम हो गया है।

दो वर्षों में 7 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता का हुआ विस्तार

सिंचाई और जल नेटवर्क

- {2 वर्षों में 7 लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ वर्तमान क्षमता 55 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जिससे लाखों नए खेतों को पानी मिला है।
- {सिंचित क्षेत्र को 100 लाख हेक्टेयर ले जाने के लक्ष्य से सूखाग्रस्त इलाकों में फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा।
- {केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल और तापी बेसिन रिचार्ज से मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़ की खेती का संकट होगा खत्म।

एग्री-बिजनेस लगाने वाले किसानों को सरकार दे रही 50% तक की भारी सब्सिडी; नरसिंहपुर और मंदसौर में कृषि उद्योग समागमों से बढ़ा औद्योगिक निवेश

धार का पीएम मित्र पार्क देगा 6 लाख कपास उत्पादकों को लाभ

भोपाल

मध्यप्रदेश को कृषि उत्पादन के साथ-साथ देश का प्रमुख एग्री-प्रसंस्करण हब बनाने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने बड़ी पहल की है। राज्य सरकार के प्रयासों से नरसिंहपुर और मंदसौर जिलों में आयोजित कृषि उद्योग समागम के बड़े परिणाम सामने आए हैं। इसके तहत कृषि आधारित नए उद्योगों को लगाने के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपये के बड़े निवेश प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है।

इस औद्योगिक क्रांति के तहत धार जिले में देश के पहले पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का सफल भूमिपूजन हो चुका है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को उन्नत बाजार और सही दाम के रूप में मिलेगा। सरकार ने कृषि आधारित कारखाने या प्रसंस्करण इकाइयां लगाने वाले स्थानीय किसानों और ग्रामीण युवाओं को बड़ी राहत दी है। इसके तहत उन्हें परियोजना लागत पर 50% तक की भारी सब्सिडी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। साथ ही, इन कारखानों में काम करने वाले स्थानीय श्रमिकों को 5,000 प्रति माह की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान है।

10 हजार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तेज

फूड पार्क, कोल्ड चैन और एग्रो-प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार कर फसलों की संपूर्ण वैल्यू चैन को मजबूत किया जा रहा है। एथेनॉल उत्पादन और मक्का आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर किसानों की उपज के लिए नए औद्योगिक बाजार विकसित किए जा रहे हैं। हर जिले में स्थानीय संसाधनों के हिसाब से एक जिला-एक उत्पाद के तहत काम हो रहा है। इसके अंतर्गत मूल्य संवर्धन के लिए 10 हजार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का कार्य तीव्र गति से जारी है। एफपीओ को मजबूत बनाकर किसानों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ दिया गया है।

टेक्नोलॉजी अपडेट

अब छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंची ड्रोन तकनीक

भोपाल। कृषि विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को नैनो-यूरिया और तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए आधुनिक कृषि ड्रोन की सेवाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। ड्रोन के उपयोग से न केवल कीटनाशकों और पानी की भारी बचत हो रही है, बल्कि समय और मजदूरी की लागत में भी कमी आई है। सरकार छोटे किसानों और स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े युवाओं को ड्रोन पायलट का विशेष प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही है।

सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण से सुधर रहा है मिट्टी का स्वास्थ्य

भोपाल। मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किस खाद की आवश्यकता है, इसकी सटीक और वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए कृषि विभाग द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। अब तक 10.76 लाख से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को पूरी तरह निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। विकासखंड स्तर पर भी 265 नई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इनका संचालन स्थानीय युवा उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे इन्हें रोजगार मिला है, तो किसानों को उनके घर के पास ही मिट्टी की सटीक जांच रिपोर्ट मिल रही है।

कृषि यंत्रीकरण में भी देश का सिरमौर बना मध्यप्रदेश

भोपाल। महंगे और आधुनिक कृषि उपकरण जैसे रोटावेटर, कंबाइन हार्वेस्टर और लेजर लैंड लेवलर छोटे किसानों को किराए पर उपलब्ध कराने के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 वर्षों हेतु 2,868 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में रिकॉर्ड 5,629 हायरिंग केंद्र सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। इन केंद्रों के माध्यम से सीमांत किसानों को बहुत कम किराए पर आधुनिक मशीनें मिल रही हैं।

एआई संग स्मार्ट फार्मिंग, मौसम व बीमारियों की सीधी जानकारी

भोपाल। मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट फार्मिंग और एआई आधारित कृषि पद्धतियों को तेज़ी से लागू किया जा रहा है। इसके तहत इंदौर में स्थापित होने वाले 1,500 करोड़ रुपये के एग्रीटेक इनोवेशन हब के माध्यम से सेटलाइट आधारित क्रॉप मैपिंग और सेंसर तकनीक को खेतों से जोड़ा जा रहा है। इस आधुनिक पद्धति के आने से किसानों को उनके स्मार्टफोन पर ही यह सटीक लाइव जानकारी मिल जाती है कि उनकी फसल में किस बीमारी की शुरुआत हो रही है या खेत के किस हिस्से में नमी कम है।

सागर और देवास के सरकारी फार्मों में उगेंगे उन्नत हाइब्रिड बीज

भोपाल

किसानों को अब अच्छी गुणवत्ता वाले सब्जी बीजों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रदेश में ही उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड सब्जी बीजों के उत्पादन की मजबूत व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी और भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर के सहयोग से दो बड़े बीजोत्पादन हब तैयार किए गए हैं। इस पहल के तहत सागर जिले के झिला फार्म पर ₹6.95 करोड़ तथा देवास जिले के कन्नौद फार्म पर ₹4.39 करोड़ की लागत से 'हाइब्रिड सब्जी बीजोत्पादन कार्यक्रम' सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। यह पहल प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सब्जी बीजों की उपलब्धता को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

तकनीक के रास्ते सफलता की ओर...खेतों में उतरी परमाणु विज्ञान की शक्ति

बार्क के सहयोग से भोपाल में लगेगी विकिरण इकाई, इंदौर को मिलेगा शीतल वाहक संयंत्र

भोपाल

मध्यप्रदेश के खेतों और बागों में अब परमाणु विज्ञान की आधुनिक तकनीक का जादू बिखरने वाला है। राज्य के उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने किसानों के चेहरों पर खुशी लाने और फसलों की शेल्फ-लाइफ (भंडारण क्षमता) बढ़ाने के लिए बड़े तकनीकी नवाचार जमीन पर उतारे हैं।

विज्ञान और पसीने के इस अनूठे संगम से अब प्रदेश के किसानों के फल-सब्जियां न सिर्फ लंबे समय तक तरोताजा रहेंगे, बल्कि वे वैश्विक बाजारों में एक्सपोर्ट के लिए भी पूरी तरह तैयार हो सकेंगे। सरकार के इन वैज्ञानिक प्रयासों ने खेती-किसानी को मुनाफे का नया सौदा बना दिया है।

इस वैज्ञानिक महा-अभियान के तहत भोपाल में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहां आम और दूसरे फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने व कीट-मुक्त निर्यात के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बार्क) बॉम्बे के सहयोग से 20 करोड़ रुपये की लागत वाली आधुनिक विकिरण तकनीकी इकाई बनाई जा रही है।

इसी तरह, इंदौर में राजारमन सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के तकनीकी सहयोग से 1.25 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक शीतल वाहक यंत्र परियोजना स्थापित की गई है। यह संयंत्र फलों और सब्जियों को लंबी दूरी के परिवहन में खराब होने से बचाएगा।

12 जिलों में आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, 10 नए जिलों में मखाने की बहार

भोपाल

व्यावसायिक खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से उज्जैन, इंदौर, सागर, छिंदवाड़ा और ग्वालियर सहित 12 प्रमुख जिलों में 2.50 करोड़ रुपये की लागत से पोटेटो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (आलू अनुबंध खेती) योजना लागू की गई है। इसी क्रम में, मखाने जैसी उच्च मूल्य की फसल को बढ़ावा देने के लिए नर्मदापुरम, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा के अलावा 10 नए जिलों-जबलपुर, कटनी, रीवा, शहडोल आदिमें मखाना क्षेत्र विस्तार योजना का विस्तार किया गया है। वहीं, संरक्षित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 6 करोड़ रुपये की लागत से 20 जिलों में 850 अल्ट्रा लो-कॉस्ट शेडनेट हाउस के निर्माण का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

पीएमएफएमई से बदली तकदीर... उज्जैन के गौरव ने लहसुन-प्याज के पाउडर से कमाया ₹16 लाख का शुद्ध मुनाफा, बुरहानपुर के अभिषेक केले से बना रहे गोल्डन पाउडर

अब खेतों से निकल रहे हैं बिजनेस टाइकून, किसानों ने खड़ी की करोड़ों की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री

भोपाल

मध्यप्रदेश का अन्नदाता अब सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपनी उपज की प्रोसेसिंग कर सीधे देश-विदेश के बाजारों में बेच रहा है। पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) और सरकारी अनुदान के सहारे सूबे के छोटे-छोटे गांवों और कस्बों से उभरे इन नए उद्यमियों ने पारंपरिक खेती के मिथकों को तोड़ दिया है। आधुनिक मशीनों, बेहतर ब्रांडिंग और पक्के इरादों के दम पर इन किसानों ने न केवल अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाया है, बल्कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोल दिए हैं। यह सफलता आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायी तस्वीर पेश करती है। **चार उदाहरणों से समझें अन्नदाता कैसे बन रहे हैं उद्योगपति**

उज्जैन के गौरव ने लहसुन-प्याज पाउडर से खड़ा किया 63 लाख का टर्नओवर

उज्जैन के प्रगतिशील युवा गौरव सिंह कनौजिया ने बाजार में मसालों और ड्राई वेजीटेबल्स की मांग को भांपकर महाकाल फूड एंड स्पाइसेस नाम से अपनी प्रोसेसिंग इकाई शुरू की। उन्होंने प्याज, लहसुन, टमाटर और चुकंदर को सुखाकर उनका पाउडर और फ्लेक्स (टुकड़े) बनाना शुरू किया।

गौरव ने योजना के तहत ₹53.41 लाख की कुल लागत से आधुनिक प्लांट लगाया, जिसमें उन्हें सरकार से ₹10.00 लाख का सीधा अनुदान मिला। तकनीक और सही मार्केटिंग के दम पर आज गौरव की इकाई का सालाना टर्नओवर ₹63.00 लाख के पार पहुंच गया है, जिससे वे हर साल ₹16.00 लाख का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं।

नीमच के सत्यनारायण ने शेडनेट से कमाया 8.46 लाख का शुद्ध लाभ

नीमच जिले के किसान सत्यनारायण पाटीदार ने अपनी खेती को मौसम की मार से सुरक्षित करने के लिए संरक्षित खेती का रास्ता चुना। उन्होंने 4000 वर्ग मीटर के रकबे में एक आधुनिक शेडनेट हाउस का निर्माण किया। इस 28.40 लाख रुपये की बड़ी परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए विभाग ने उन्हें 14.20 लाख रुपये की 50% भारी सब्सिडी दी। सत्यनारायण ने शेडनेट के भीतर खीरा-ककड़ी का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। अनुकूल वातावरण के कारण फसल की बंपर पैदावार हुई और उन्होंने मात्र दो सीजन में ही 14.06 लाख रुपये की कुल आय के साथ 8.46 लाख रुपये का शुद्ध वार्षिक लाभ अर्जित किया।

केला हब बुरहानपुर में अभिषेक ने केले से बनाया गोल्डन पाउडर, 6 को रोजगार

केला उत्पादन के लिए मशहूर बुरहानपुर जिले के अभिषेक जयसवाल ने कच्चे केलों की बर्बादी को रोकने के लिए लाला हार्वेस्ट नाम से एक अनूठी इकाई स्थापित की। वे प्रतिदिन 40 किलो केला पाउडर और 20 किलो प्याज के फ्लेक्स तैयार कर रहे हैं। इस प्लांट के लिए उन्हें 19.94 लाख रुपये की बैंक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। आज इस बिजनेस से वे 4.80 लाख रुपये की शुद्ध वार्षिक आय कमा रहे हैं। अभिषेक की इस इकाई का सबसे खूबसूरत पहलू इसका सामाजिक प्रभाव है, जहाँ उन्होंने स्थानीय स्तर पर 6 ग्रामीण युवाओं को नियमित और सम्मानजनक रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया है।

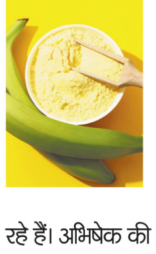

अनूपपुर की रीता बनीं मिसाल, 1 लाख की मदद से खड़ा किया ₹10 लाख का बिजनेस

महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की सबसे शानदार कहानी अनूपपुर जिले की रीता सिंह ने लिखी है। उन्होंने ग्रामीण अंचल में उपलब्ध औषधीय संसाधनों का उपयोग कर 'श्री ज्ञानम आंवला मुरब्बा एवं मसाला उद्योग' की शुरुआत की। रीता ने महज 1.04 लाख रुपये की सरकारी वित्तीय सहायता से अचार, पारंपरिक मसाले, बेकरी उत्पाद और आंवला मुरब्बा प्रसंस्करण का काम शुरू किया। उनके उत्पादों की शुद्धता के कारण बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ी। आज रीता सिंह 10.00 लाख की शुद्ध वार्षिक आय हासिल कर क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं के लिए स्वरोजगार की सबसे बड़ी रोल मॉडल बन चुकी हैं।